न्यायमूर्ति एन. सी. जैन के समक्ष

सुमेधा कालिया (सुश्री) और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाता

सिविल रिट याचिका सं. 11980/1989.

22 जनवरी, 1990

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226 और 227- महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक एमबीबीएस /बीडीएस प्रवेश परीक्षा, 1989 के लिए प्रॉस्पेक्टस - नोट 1 पी 6, सीएच 2, सीएच 5 रेग नंबर 4 - संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस /बीडीएस में प्रवेश - सी.बी.एस.ई अखिल भारतीय आधार पर उम्मीदवारों को प्रायोजित नहीं करना - खाली पड़ी सीटें - ऐसी सीटों को भरने की कानूनी बाध्यता - समय की कमी के कारण याचिकाकर्ताओं को योग्यता के आधार पर पेश की जाने वाली खाली सीटें।

अभिनिर्धारित किया कि, याचिकाकर्ताओं को खाली पड़ी सीटों पर भर्ती करने का कानूनी अधिकार है। उत्तरदाताओं को खाली सीटों को भरने के लिए अपने हिस्से का कर्तव्य निभाने के लिए कानूनी दायित्व मिला है। एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नियम हमेशा प्रॉस्पेक्टस में निहित होते हैं जो हर साल जारी किए जाते हैं। एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस में, अध्याय II में सीटों की संख्या निर्दिष्ट की गई है। इन्हें संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर भरा जाना है। प्रॉस्पेक्टस के अध्याय 5 में विनियम संख्या 4 के अनुसार, सभी सीटों को एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को प्रवेश देकर भरा जाना है और इस विनियमन में एमबीबीएस एस/बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए योग्यता के क्रम में और आवेदन पत्र में दी गई वरीयता के अनुसार और व्यक्तिगत पाठ्यक्रम के लिए सीटों की उपलब्धता के अधीन एक सामान्य मेरिट सूची तैयार करने की परिकल्पना की गई है। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ताओं का कानूनी अधिकार विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस में किए गए प्रावधानों से आता है। प्रॉस्पेक्टस

जारी होने के बाद ही कोई उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित होता है और इसलिए, ऐसे उम्मीदवार से यह पूछना बहुत अधिक होगा कि विश्वविद्यालय उसे प्रवेश नहीं देगा, भले ही वह प्रवेश का हकदार हो और भले ही उसने प्रॉस्पेक्टस के आधार पर काम किया हो। इस न्यायालय के विचार में, प्रॉस्पेक्टस में प्रावधान करना विश्वविद्यालय पर एक कानूनी कर्तव्य डालता है कि वह उन छात्रों को प्रवेश दे जो अन्यथा सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं। दूसरे शब्दों में, विश्वविद्यालय खुद को प्रॉस्पेक्टस की शर्तों से बांधता है और इसे यह तर्क देने के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि छात्रों को प्रवेश देने के लिए उस पर कोई कानूनी कर्तव्य नहीं डाला गया है, भले ही वे सभी योग्यताओं को पूरा कर रहे हों।

(अनुच्छेद 8)

अभिनिर्धारित किया कि, यह तर्क कि विश्वविद्यालय को सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली के लिए निर्धारित सीटों को खुली श्रेणी में बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, किसी भी योग्यता से रहित है। एक बार स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, नई दिल्ली ने अधिकारियों को सूचित किया है कि सी.बी.एस.ई. अग्रोहा मेडिकल कॉलेज संस्थान के लिए किसी भी सीट को प्रायोजित नहीं कर रहा है, इसे प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए खोला जा सकता है, पहले सिद्धांत पर कि कोई भी सीट बर्बाद नहीं होनी चाहिए।

(अनुच्छेद 9)

अभिनिर्धारित किया कि, उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश का समय बहुत पहले खत्म हो गया था और याचिकाकर्ताओं के अलावा प्रतीक्षा-सूची वाले उम्मीदवारों में से कोई भी अपने दावे पर जोर देने के लिए आगे नहीं आया है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आमतौर पर अधिक मेधावी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन लंबा समय बीत चुका है। जिन याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें देरी के कारण और अधिक पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, यह आदेश दिया जाता है कि जिन उम्मीदवारों ने अब तक इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें उनकी योग्यता के क्रम में प्रवेश दिया जाए। यह एकमात्र तरीका है जिस पर यह न्यायालय विचार कर पाया है, उन याचिकाकर्ताओं को पूर्ण राहत प्रदान करना उचित होगा जिन्होंने इस न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों का आंदोलन किया है।

(अनुच्छेद 11)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय निम्नलिखित के लिए कृपा करे: -

1) उत्तरदाताओं संख्या 2 और 3 के रिकॉर्ड भेजें;

2) एक रिट ऑफ मेंडिमेशन जारी कर प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया है कि एमबीबीएस और बीडीएस प्रवेश परीक्षा के लिए पीएमटी-टेस्ट आयोजित करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा तैयार मेरिट सूची में से वर्ष 1989-90 के लिए मेडिकल कॉलेज, रोहतक और मेडिकल इंस्टीट्यूट, अग्रोहा और डेंटल कॉलेज, यमुना नगर में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 21 सीटें भरी जाएं और याचिकाकर्ताओं को संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाए;

3) इस मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे जाने वाले किसी अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश को जारी करना;

4) प्रतिवादियों को प्रस्ताव के नोटिस की पूर्व सेवा को समाप्त करें क्योंकि इसके आग्रह से रिट याचिका निरर्थक हो जाएगी;

5) अनुलग्नक के रूप में संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करना;

6) याचिकाकर्ताओं को इस रिट याचिका की लागत प्रदान करना।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एल. सिब्बल और अधिवक्ता आई. एस. बलहारा उपस्थित थे।

जे. एल. गुप्ता, एडवोकेट, जसवंत सिंह, एडवोकेट और विक्रांत शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादियों के लिए।

मदन देव, एडवोकेट, एजी हरियाणा के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति नरेश चंद्र जैन:-

1. मेरा यह निर्णय सिविल रिट याचिका संख्या 11980, 14858, 14904, 15645, 12658 का निपटारा करेगा। इन सभी रिट याचिकाओं में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न के रूप में 12627, 12794, 13569, 13448, 13945, 14903, 14252, 15067, 16113, 16640 और 19एस0 के 43 कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न के रूप में शामिल हैं। इस न्यायालय को बताया गया है कि 1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 48 में हाल ही में नोटिस जारी किया गया है और वकील विश्वविद्यालय से निर्देश प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। यह सच होना चाहिए, लेकिन यह न्यायालय किसी भी रिट याचिका को स्थगित करने का इच्छुक नहीं है क्योंकि इन रिट याचिकाओं में जो भी राहत दी जा रही है, उपरोक्त रिट याचिका में याचिका उसी शर्त के अधीन हकदार होगी कि याचिकाकर्ता ने खुली प्रवेश परीक्षा में अपनी योग्यता के संबंध में सही तथ्यात्मक स्थिति दर्शाई है। पार्टियों के वकील इस बात से सहमत हैं कि विवाद में प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए मामले के बुनियादी तथ्यों को 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 11980 मिस सुमेधा कालिया और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य से उठाया जा सकता है।

2. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के प्रतिवादी संख्या 2 ने 1989 के मिस सुमेधा कालिया और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के सीडब्ल्यूपी नंबर 11980 में वर्ष 1989-90 के लिए एमबीबीएस / बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की। एम.बी.बी.एस/बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या जैसा कि प्रॉस्पेक्टस में दिया गया है, निम्नानुसार है: -

"एमबीबीएस कोर्स:

i. मेडिकल कॉलेज, रोहतक

सीबीएसई, नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय आधार पर 115 सीटें (98 विश्वविद्यालय द्वारा भरी जानी हैं और 17 सीटें (13 सीटें खुली + 4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए) हैं।

आरक्षित - 49 सीटें

ओपन मेरिट = 49 सीटें

ii. अग्रोहा चिकित्सा संस्थान, अग्रोहा

50 सीटें (विश्वविद्यालय द्वारा भरी जाने वाली 42) और 8 (एस के लिए 6 खुली + 2)। (ग/एसटी) सीबीएसई, नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय आधार पर)।

आरक्षित = 21

ओपन मेरिट = 21

बी.डी.एस. कोर्स

i. डेंटल कॉलेज, रोहतक

20 सीटें (17 सीटें विश्वविद्यालय द्वारा भरी जानी हैं और 3 सीटें (एससी / एसटी के लिए 2 खुली + 1) सीबीएसई, दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय आधार पर)।

आरक्षित = 6 सीटें

ओपन मेरिट = 11 सीटें

ii. डी.ए.वी. शताब्दी डेंटल कॉलेज, यमुनानगर: 22 सीटें

आरक्षित = 8 सीटें

ओपन = 14 सीटें"

उपर्युक्त तालिका से, यह स्पष्ट है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सीटों की कुल संख्या 165 है, जिसमें से 115 सीटें मेडिकल कॉलेज रोहतक के लिए हैं और 50 सीटें अग्रोहा मेडिकल इंस्टीट्यूट, अग्रोहा के लिए हैं। मेडिकल कॉलेज रोहतक के लिए निर्धारित 115 सीटों में से 98 सीटें विश्वविद्यालय द्वारा भरी जानी हैं, जबकि 17 सीटें अखिल भारतीय आधार पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (संक्षेप में, सीबीएसई), नई दिल्ली द्वारा भरी जानी हैं, बदले में, उक्त 17 सीटों में से 13 सीटें खुली श्रेणी से भरी जानी हैं जबकि 4 सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से

भरी जानी हैं। जहां तक अग्रोहा चिकित्सा संस्थान, अग्रोहा का संबंध है, उक्त 50 सीटों में से 42 सीटें विश्वविद्यालय द्वारा भरी जानी हैं और 8 सीटें सीबीएसई, नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय आधार पर भरी जानी हैं। सीबीएसई द्वारा भरी जाने वाली आठ सीटों में से छह सीटें खुली श्रेणी के लिए खोल दी गई हैं, जबकि दो एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। जहां तक बीडीएस पाठ्यक्रम का संबंध है, 20 सीटें डेंटल कॉलेज, रोहतक के लिए हैं जबकि 22 सीटें डीएवी शताब्दी डेंटल कॉलेज, यमुनानगर द्वारा भरी जानी हैं। अग्रोहा चिकित्सा संस्थान अग्रोहा में कॉलेज नहीं है और इसलिए, इसके लिए निर्धारित सीटों को भरा जाना है और चिकित्सा संस्थान, रोहतक द्वारा पूर्व में भरा गया था। इस तथ्यात्मक स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उल्लिखित संस्थानों की सूची में अग्रोहा चिकित्सा संस्थान, अग्रोहा का नाम कोई उल्लेख नहीं है। मेडिकल कॉलेज, रोहतक की 115 सीटों में से अखिल भारतीय कोटे से 9 सीटें खाली पड़ी हैं और एक सीट एक छात्र संजय दुहन की रिट याचिका स्वीकार होने के कारण उसके शिलिंग के बाद खाली हो गई है। अग्रोहा चिकित्सा संस्थान की 50 सीटों में से 10 सीटें खाली पड़ी हैं जिन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। दोनों पक्षों के वकील के अनुसार, रोहतक में एमई बाई>3 कोर्स में 5 सीटें खाली पड़ी हैं। इन पांच सीटों में से तीन सीटें सीबीएसई द्वारा अखिल भारतीय आधार पर भरी जानी हैं और एक सीट भारत सरकार के नामांकित व्यक्ति के माध्यम से भरी जानी है, जबकि शेष एक को एससी/एसटी की श्रेणी से भरा जाना है, जैसा कि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा मेरे समक्ष तर्क दिया गया है।

3. उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति को इस अदालत के समक्ष कुल मिलाकर स्पष्ट किया गया था, लेकिन साथ ही प्रतिवादियों के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि सीटों की उपलब्धता याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा किए जा रहे दावे से कम है, जबकि याचिकाकर्ताओं के वकील का विचार था कि सीटों की उपलब्धता बहुत अधिक है। हालांकि, तथ्यात्मक स्थिति पर विवाद इस अदालत को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रवेश वास्तव में उपलब्ध सीटों के खिलाफ ही किया जाएगा। इस अदालत को केवल याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का निर्धारण करना है और उसके बाद याचिकाकर्ताओं के प्रवेश के संबंध में कानून अपना काम करेगा।

4. रिट याचिकाओं के प्रवेश के बाद, कुछ याचिकाकर्ताओं को अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर अनंतिम प्रवेश दिया गया था। कुछ याचिकाकर्ताओं की नाराजगी जिन्हें अनंतिम प्रवेश नहीं दिया गया था, यह था कि उन्हें अस्थायी प्रवेश देने से इनकार करके, प्रतिवादियों ने अदालत की अवमानना की है। रिट याचिकाओं और अवमानना याचिकाओं की सुनवाई के समय, पक्षकारों के वकील ने इस बिंदु पर अपनी तलवारें पार कीं कि क्या प्रतिवादी इस अदालत की अवमानना करने के दोषी हैं या नहीं। जहां तक याचिकाकर्ताओं के अधिकारों के निर्धारण का संबंध है, अवमानना कार्यवाही शुरू करने और उसमें तथ्यात्मक स्थिति पर विवाद भी मुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अंततः इस अदालत को केवल याचिकाकर्ताओं के उन सीटों पर भर्ती होने के अधिकारों का फैसला करना है जो खाली रह गई हैं। एक बार जब यह निर्णय हो जाता है कि याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज, रोहतक और अग्रोहा मेडिकल इंस्टीट्यूट, अग्रोहा में एमबीबीएस /बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के हकदार हैं, तो यह शायद ही कोई सामग्री होगी कि क्या अधिकारी सीटों की उपलब्धता के बारे में कुछ भ्रम के कारण आदेशों का पालन करने में सक्षम नहीं हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कोटे आदि को ध्यान में रखते हुए सीटों के विभिन्न समायोजनों के कारण। केवल इसी कारण से यह न्यायालय प्राधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को कम करने का इच्छुक नहीं है और एक झटके में यह कहा जा सकता है कि इस न्यायालय के आदेशों की कोई अवज्ञा नहीं की गई थी।

5. मामले के गुण-दोष पर विचार करने से पहले, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अग्रोहा में, कोई चिकित्सा संस्थान नहीं है और मेडिकल कॉलेज रोहतक 50 छात्रों को प्रवेश देता है। यह अतीत में किया गया था। दूसरे शब्दों में, अग्रोहा मेडिकल इंस्टीट्यूट अग्रोहा को एक अतिथि संस्थान के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यहां तक कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में भी लगभग 40 सीटें पहले ही भरी जा चुकी हैं। शेष सीटों को भरने का कार्य अभी किया जाना है।

6. मामले के गुण-दोष के आधार पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने प्रवेश परीक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा की थी और उत्तरदाताओं द्वारा अधिसूचित प्रतीक्षा सूची में हैं, वे अब खाली पड़ी सीटों के खिलाफ प्रवेश पाने के हकदार हैं।

दूसरे शब्दों में, तर्क यह है कि याचिकाकर्ता खाली पड़ी सभी सीटों पर भर्ती होने के हकदार हैं, चाहे वे मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में हों, जहां वे सीबीएसई द्वारा संक्षेप में किसी भी छात्र को प्रायोजित नहीं करने के कारण खाली पड़े हैं, याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क यह है कि एक बार महानिदेशक (स्वास्थ्य सेवा) ने अखिल भारतीय आधार पर किसी भी छात्र को प्रायोजित नहीं किया है, विश्वविद्यालय को उन सीटों को खुली श्रेणी में मानकर प्रतीक्षा सूची से छात्रों को प्रवेश देना होगा। यह भी तर्क दिया गया है कि सीबीएसई कोटा के अलावा विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित सभी सीटें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा जारी एमबीबीएस/बीडीएस प्रवेश परीक्षा, 1989 के लिए प्रॉस्पेक्टस के पृष्ठ 6 पर नोट 1 के मद्देनजर ओपन मेरिट उम्मीदवारों से भरी जानी चाहिए। रोहतक, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> उन्होंने कहा, "आरक्षित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा उन श्रेणियों के उम्मीदवारों के बीच होगी जिनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण खाली रहने वाली आरक्षित सीटों को 'ओपन मेरिट' सीटों के तहत रखा जाएगा।

आगे यह तर्क दिया गया है कि पिछले वर्षों में भी, ऐसी सभी सीटें जो किसी न किसी श्रेणी के आगे नहीं आने के कारण उपलब्ध हुई थीं, उन्हें खुली मेरिट में उम्मीदवारों के लिए खोल दिया गया था, और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कानून का जनादेश है कि कोई भी सीट बेकार नहीं जानी चाहिए और यदि कोई सीट बर्बाद हो रही है, इसका उपयोग उन उम्मीदवारों द्वारा किया जाना चाहिए जो खुली मेरिट में प्रवेश के हकदार हैं।

7. रिट याचिकाओं का बचाव करते हुए, प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि छात्रों के पास विश्वविद्यालय के खिलाफ परमादेश जारी करने का दावा करने का कोई वैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है और विश्वविद्यालय पर कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं डाला गया है जो इसे छात्रों को प्रवेश देने के लिए मजबूर कर सके। आगे यह तर्क दिया गया है कि भले ही विश्वविद्यालय प्रॉस्पेक्टस से बाध्य हो, लेकिन अग्रोहा में सीटों का दावा छात्रों द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे विश्वविद्यालय द्वारा केवल सीबीएसई परीक्षा देने वाले

उम्मीदवारों से भरे जाने के लिए आरक्षित थे; किसी भी मामले में विश्वविद्यालय को सीबीएसई कोटा से सामान्य श्रेणी में सीटों को मोड़ने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से कोई निर्देश या परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक आवश्यकता और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक कट-ऑफ तारीख तय की थी, और उस तारीख की समाप्ति के लंबे समय बाद, छात्रों को संस्थान में प्रवेश देने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। आगे यह तर्क दिया गया है कि अग्रोहा मेडिकल इंस्टीट्यूट, अग्रोहा में दस सीटों में से आठ को सीबीएसई कोटे से भरा जाना था, एक अनुसूचित जाति /जनजाति की श्रेणी से और दूसरा भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले छात्र को प्रवेश देकर। प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया कि सभी सीटें सामान्य श्रेणी के लिए नहीं खोली जा सकती हैं। इस स्तर पर, यह देखा जा सकता है कि प्रतिवादियों के वकील द्वारा यह विवादित नहीं किया गया है कि भारत सरकार ने उपरोक्त सीटों के खिलाफ कोई नाम नहीं भेजा है। दूसरी ओर, यह स्वीकार किया गया है कि महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली ने लिखा है कि सीबीएसई, नई दिल्ली अग्रोहा चिकित्सा संस्थान, अग्रोहा की 50 सीटों में से किसी भी सीट का दावा नहीं कर रहा है। हो सकता है, प्रतिवादियों के वकील का यह रुख सही हो कि अग्रोहा मेडिकल इंस्टीट्यूट को मान्यता न दिए जाने के कारण सीबीएसई किसी भी सीट को प्रायोजित नहीं कर रहा है, फिर भी तथ्य यह है कि सीबीएसई सीबीएसई कोटा में से किसी भी सीट को प्रायोजित नहीं कर रहा है, और इसलिए, इन परिसरों में यह निर्णय लिया जाना है कि क्या इन सीटों को खुली श्रेणी के लिए खोला जा सकता है और इन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रतीक्षा सूची में शामिल छात्र।

8. पक्षकारों के वकीलों की दलीलों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ताओं को रिक्त पड़ी सीटों पर प्रवेश पाने का कानूनी अधिकार है। उत्तरदाताओं को खाली सीटों को भरने के लिए अपने हिस्से का कर्तव्य निभाने के लिए कानूनी दायित्व मिला है। एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विनियम हमेशा विवरणिका में निहित होते हैं जो हर साल जारी किए जाते हैं। एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस में, अध्याय II में सीटों की संख्या निर्दिष्ट की गई है।

इन्हें संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर भरा जाना है। प्रॉस्पेक्टस के अध्याय 5 में विनियम संख्या 4 के अनुसार, सभी सीटों को एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को प्रवेश देकर भरा जाना है और इस विनियमन में एमबीबीएस / बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए योग्यता के क्रम में और आवेदन पत्र में दी गई वरीयता के अनुसार और व्यक्तिगत पाठ्यक्रम के लिए सीटों की उपलब्धता के अधीन एक सामान्य मेरिट सूची तैयार करने की परिकल्पना की गई है। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ताओं का कानूनी अधिकार विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस में किए गए प्रावधानों से आता है। प्रॉस्पेक्टस जारी होने के बाद ही कोई उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित होता है और इसलिए; ऐसे उम्मीदवार से यह पूछना बहुत ज्यादा होगा कि विश्वविद्यालय उसे प्रवेश नहीं देगा, भले ही वह प्रवेश पाने का हकदार हो और भले ही उसने प्रॉस्पेक्टस के आधार पर काम किया हो। इस न्यायालय के विचार में, प्रॉस्पेक्टस में प्रावधान करना विश्वविद्यालय पर एक कानूनी कर्तव्य डालता है कि वह उन छात्रों को प्रवेश दे जो अन्यथा सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं। दूसरे शब्दों में, विश्वविद्यालय खुद को प्रॉस्पेक्टस की शर्तों से बांधता है और इसे यह तर्क देने के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि छात्रों को प्रवेश देने के लिए उस पर कोई कानूनी कर्तव्य नहीं डाला गया है, भले ही वे सभी योग्यताओं को पूरा कर रहे हों। कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियों में, राज्य सरकार को उड़ीसा राज्य बनाम डा असीम कुमार मोहंती[1] मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विवरणिका की शर्तों से बाध्य ठहराया गया था और डा जीवक अलमस्त बनाम भारत संघ तथा अन्य[2] मामले में भी इस आशय की विशिष्ट टिप्पणी की गई थी। शीर्ष अदालत ने उन रिक्त सीटों को भरने के निर्देश जारी किए जो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या के कारण खाली रह गई थीं। उच्चतम न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणी को निम्नानुसार देखा और पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है: -

पीठ ने कहा, 'विचार का सवाल यह है कि क्या इन खाली सीटों को संबंधित राज्यों और/या संस्थानों को वापस कर दिया जाना चाहिए या रिक्तियों को भरने के लिए क्या अन्य तरीका

[1] ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 1801.
[2] ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 1812.

अपनाया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई है और सभी पक्षों के बीच इस बात पर पूरी सहमति है कि कोई भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। यह सर्वविदित है कि हमारे देश में पर्याप्त संख्या में योग्य डाक्टर नहीं हैं और इसलिए अधिक से अधिक स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले डाक्टरों को बाहर करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाना चाहिए। इसके लिए समस्या यह है कि इन खाली आरक्षित सीटों को भरने के लिए क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए।

इसी तरह का विचार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमनजीत सिंह गिल बनाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के मामले में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में व्यक्त किया था[3]। सभी तय किए गए मामलों में अनुपात यह प्रतीत होता है कि कोई भी सीट बेकार नहीं जानी चाहिए और इसे ध्यान में रखते हुए, यह तर्क देना व्यर्थ है कि याचिकाकर्ताओं के पास रिक्त सीटों को भरने के लिए परमादेश का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादी के वकील का यह तर्क कि विश्वविद्यालय कट-ऑफ तिथि समाप्त होने के बाद प्रवेश देने के लिए बाध्य नहीं है, समान रूप से अस्थिर है। यदि सीटें उपलब्ध हैं, और वे किसी न किसी कारण से भरी नहीं गई हैं, चाहे वे कारण अधिकारियों के नियंत्रण में थे या उनके नियंत्रण से बाहर थे, तो यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि ऐसी सीटें बेकार जानी चाहिए। कट ऑफ तिथियों के बाद प्रवेश नहीं देने के सिद्धांत को किसी भी न्यायिक घोषणा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। दूसरी ओर, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्णयों और विशेष रूप से विनय शंकर आदि बनाम महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में निर्धारित कानून का अनुपात [4] यह प्रतीत होता है कि अदालत हमेशा प्रवेश का आदेश दे सकती है और विनय शंकर के मामले (सुप्रा) में ठीक यही किया गया है। शीर्ष अदालत ने छात्रों के स्थानांतरण और उनके प्रवेश आदि के लिए कई तारीखें तय की हैं।

9. खाली पड़ी सीटों पर प्रवेश लेने के लिए याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का निपटारा करने के बाद, इस न्यायालय द्वारा यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या अग्रोहा मेडिकल कॉलेज संस्थान

[3] ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 386.

[4] सी.डब्ल्यू.पी. 1989 के 1253 का निर्णय 20 दिसम्बर 1989 को हुआ।

में खाली पड़ी सीटें और जिन्हें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है, को उन याचिकाकर्ताओं के लिए खोला जा सकता है जो खुली मेरिट में प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस संबंध में प्रतिवादी के वकील का यह तर्क कि विश्वविद्यालय को सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली के लिए निर्धारित सीटों को खुली श्रेणी में बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, किसी भी योग्यता से रहित है। एक बार जब स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली ने अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि सी.बी.एस.ई. अग्रोहा मेडिकल कॉलेज संस्थान को कोई भी सीट प्रायोजित नहीं कर रहा है, तो इसे प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए खोला जा सकता है, पहले सिद्धांत पर कि कोई भी सीट बर्बाद नहीं होनी चाहिए, जैसा कि शीर्ष अदालत ने डॉ. जीवक लगभग के मामले (सुप्रा) में देखा है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए और विशेष रूप से डॉ. जीवक अलमस्ट्स मामले (सुप्रा) में यह सुरक्षित रूप से कानून के एक बिंदु पर रखा जा सकता है कि कोई भी सीट बेकार नहीं जानी चाहिए और इसलिए, अदालत आदेश दे सकती है कि खाली सीटों को उन उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए खोल दिया जाए जो खुली श्रेणी में प्रतीक्षा सूची में हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था और यह सही था कि अतीत में भी खाली सीटों को खुली श्रेणी में फेंक दिया गया था और प्रतीक्षा सूची के छात्रों को प्रवेश दिया गया था। इस रुख का विरोध नहीं किया गया था, लेकिन यह प्रस्तुत किया गया था कि विश्वविद्यालय कॉलेज की मान्यता रद्द करने का सामना कर रहा है। जहां तक रोहतक मेडिकल कॉलेज की अपेक्षा अधिक छात्रों को प्रवेश देने के कारण मान्यता रद्द करने का प्रश्न है, इस सिद्धांत की इस न्यायालय द्वारा कम से कम सराहना की गई है। पूर्व में भी अग्रोहा चिकित्सा संस्थान के लिए निर्धारित सीटें। अग्रोहा को मेडिकल कॉलेज रोहतक द्वारा भरा जा रहा था। इस वर्ष भी 40 सीटें खाली रह गई हैं। यदि मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया हुई है तो यह पहले ही किया जा चुका है। अधिक छात्रों के प्रवेश का मतलब यह नहीं होगा कि किसी नए अयोग्य को अयोग्य घोषित किया जाएगा।

10. अब देखना यह है कि याचिकाकर्ता किस राहत के हकदार हैं। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में याचिकाकर्ता अग्रोहा चिकित्सा संस्थान, अग्रोहा में सीटों पर भर्ती होने के हकदार

हैं क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है। जहां तक अन्य सीटों का संबंध है जो अखिल भारतीय प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर अखिल भारतीय कोटे में नहीं आती हैं और जिन्हें सी बी ई ई नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित नहीं किया जाना है, उन्हें भी तत्काल भरा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ताओं को खुली श्रेणी के उम्मीदवारों से अग्रोहा मेडिकल इंस्टीट्यूट में सी.बी.आर.ई. के लिए उत्तरदाताओं द्वारा आरक्षित सीटों पर प्रवेश देना चाहिए। जहां तक रोहतक मेडिकल कॉलेज, रोहतक में रिक्त नहीं पड़ी सीटों का संबंध है और जिनकी सूची विनेव शंकर के मामले (सुप्रा) में उच्चतम न्यायालय के निदेशों के आलोक में अभी तक नहीं आई है, प्राधिकारी 8 फरवरी, 1990 के बाद उन सीटों को भरेंगे जो सी बी ई द्वारा प्रायोजित नहीं हैं। नई दिल्ली। दूसरे शब्दों में, जो भी सीटें उपलब्ध हैं, वे सी बी ई नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित किए जाने के अनुसरण में सीटों को भरने के बाद 8 फरवरी, 1990 को बदल जाती हैं, उन्हें 8 फरवरी, 1990 को भर दिया जाएगा। कोई भी सीट जो किसी विशेष उम्मीदवार के किसी कारण से शामिल न होने की स्थिति में रिक्त रहती है या रिक्त हो जाती है, उसे भी विश्वविद्यालय द्वारा भरा जाएगा। ऊपर दिए गए दृष्टिकोण में, परमादेश की एक रिट जारी की जाती है, जिसमें प्रतिवादी-प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान में रिक्त पड़ी सीटों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई मेरिट के आधार पर छात्रों को तुरंत प्रवेश दें। यह भी कहा जाता है कि 8 फरवरी, 1990 के बाद विनय शंकर के मामले (सुप्रा) में जो भी सीटें खाली रहती हैं, उन्हें भी बिना किसी देरी के भरा जाए। यह भी निर्देश दिया जाता है कि कोई भी सीट जो किसी भी कारण से अधिकारियों के लिए उपलब्ध हो गई है, उसे भी बिना किसी देरी के भरा जाएगा। ये टिप्पणियां सभी संस्थानों पर लागू होंगी।

11. फैसले से अलग होने से पहले, यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या ओपन मेरिट प्रतीक्षा सूची में छात्रों को सीटों की पेशकश की जानी है या क्या यह है कि प्रवेश केवल याचिकाकर्ताओं को दिया जाना है जिन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, इस संबंध में यह देखा गया है कि शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश का समय बहुत पहले समाप्त हो गया था और याचिकाकर्ताओं के अलावा प्रतीक्षा-सूची वाले उम्मीदवारों में से कोई भी नहीं था। वह अपने दावे

पर जोर देने के लिए आगे आए हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आमतौर पर अधिक मेधावी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन चूंकि लंबा समय बीत चुका है, इसलिए जिन याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें देरी के कारण अधिक पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, यह आदेश दिया जाता है कि जिन उम्मीदवारों ने अब तक इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें उनकी योग्यता के क्रम में प्रवेश दिया जाए। यह एकमात्र तरीका है जिसके बारे में यह न्यायालय सोच पाया है, उन याचिकाकर्ताओं को पूर्ण राहत प्रदान करना उचित होगा जिन्होंने इस न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों का आंदोलन किया है।

12. एक और सवाल जो इस न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए आता है, वह यह है कि "क्या याचिकाकर्ता अजीब तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए व्याख्यान की कमी के लिए माफी के हकदार हैं या नहीं? मामले के इस पहलू पर, यह सीधे देखा जा सकता है कि जो भी देरी हुई है, उसे याचिकाकर्ताओं की ओर से किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह विलंब या तो अग्रोहा चिकित्सा संस्थान, अग्रोहा में रिक्त पड़ी सीटों को न भरने के प्राधिकारियों के रवैये के कारण हुआ है जबकि सी बी एस ई उन सीटों पर कोई दावा नहीं कर रहा था। रोहतक मेडिकल कॉलेज, रोहतक में सीबीएसई द्वारा उचित समय के भीतर उम्मीदवारों को प्रायोजित नहीं करने के कारण याचिकाकर्ताओं के साथ कोई गलती नहीं पाई जा सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, न्यायिक विवेक का उपयोग स्पष्ट टिप्पणी करके किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को देर से प्रवेश के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं को विश्वविद्यालय या कॉलेज के अधिकारियों द्वारा व्याख्यान की कमी के लिए माफी की अनुमति दी जा सकती है या वे किसी भी प्रावधान को बनाने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या किसी अन्य उच्च प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं जो व्याख्यान को माफ करने के लिए उपयुक्त माना जाता है यदि विश्वविद्यालय या कॉलेज के अधिकारियों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है।

ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में, रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ताओं

को निर्णय के पैरा 10 और एन में की गई टिप्पणियों के आलोक में एमबीबीएस / बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाए। कोई कीमत नहीं। दिए जाने वाले फैसले की प्रति- अपेक्षित नकल परिवर्तनों के भुगतान पर दस्ती।

पी.सी.जी.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

यमुनानगर, हरियाणा